जी-20 घोषणा-पत्र

1. हम जी-20 के नेता 18-19 जून, 2012 को लॉस काबोस में मिलें।

2. हम विकास और नौकरियों को बढ़ावा देने का संयुक्त रूप से संकल्प व्यक्त करते हैं।

3. हमारी पिछली बैठक के बाद से वैश्विक आर्थिक सुधार के समक्ष अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न होती रहीं हैं। वित्तीय बाज़ार में बहुत तनाव है। विदेशी, राककोषीय और वित्तीय संतुलन विद्यमान है जिनका विकास और रोजगार की संभावनाओं तथा भरोसे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। स्पष्ट है कि विश्व अर्थव्यवस्था कमजोर बनी हुई है और पूरे विश्व में लोगों के जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है जिससे नौकरियाँ, व्यापार, विकास और पर्यावरण भी प्रभावित हो रहे हैं।

4. हम आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को मजबूत बनाने और वित्तीय बाज़ार के तनावों को कम करने हेतु मिल कर कार्य करेंगे।

5. विकास एवं वित्तीय स्थायित्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हम मांग की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने और भरोसा बहाल करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करेंगे ताकि हमारे नागरिकों के लिए अच्छी नौकरियों एवं अवसरों का सृजन हो सके। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से आज हमने समेकित लॉस काबोस विकास एवं नौकरी कार्य योजना पर अपनी सहमति व्यक्त की।

6. जी-20 के यूरो क्षेत्र के सदस्य इस क्षेत्र की अखंडता और स्थिरता को संरक्षित रखने, वित्तीय बाज़ारों के कार्यकरण में सुधार लाने तथा संप्रभु ऋण और बैंको के बीच सूचना की कमी को समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक नीतिगत उपाय करेंगे। हम चाहते हैं कि यूरो क्षेत्र के देश ग्रीस की अगली सरकार के साथ मिलकर कार्य करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे यूरो क्षेत्र के भीतर सुधार और निरंतरता के मार्ग पर बने रहें।

7. हम मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं को बढ़ावा देने तथा और भी रोचनीय वित्तीय प्रणाली का निर्माण करने के लिए अपनी ढांचागत एवं नियामक सुधार कार्यसूची को कार्यान्वित कर रहें हैं। हम घाटे वाले देशों में सार्वजनिक वित्त प्रणाली को ठोस एवं सतत नीतियों के जरिये मजबूत बनाकर असंतुलन की समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस समाधान में उभरती आर्थिक परिस्थितियों तथा विशाल चालू खाता आधिक्य वाले देशों में घरेलू मांग को बढ़ावा देकर तथा बेहतर विनिमय दर लोचनीयता को बढ़ावा देकर प्राप्त किया जा सकता है।

8. घरेलू स्तर पर विद्यमान चुनौतियों के बावजूद हमने इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त की है कि वर्तमान परिवेश में बहुपक्षवाद और भी महत्वपूर्ण है और यह वैश्विक आर्थिक कठिनाइयों का समाधान करने के लिए सर्वोत्तम संसाधन उपलब्ध कराता है।

9. विकासशील देशों, खास कर अल्प आय वाले देशों पर इस सतत संकट के प्रभावों को स्वीकार करते हुए हम विकास, जिसमें अवसंरचना निवेश का समर्थन भी शामिल है, के लिए और भी अनुकूल परिवेश का सृजन करने संबंधी अपने प्रयासों में तेज़ी लाएँगे। हमारी नीतिगत कार्रवाइयों से पूरे विश्व में रहन-सहन की स्थितियों में सुधार आएगा और सबसे कमजोर देशों का संरक्षण हो सकेगा। विशेषकर, वैश्विक बाज़ारों में स्थिरता लाकर तथा ठोस विकास को बढ़ावा देकर हम पूरे विश्व में विकास तथा गरीबी उपशमन के संबंध में महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभावों का भी सृजन कर सकेंगे।

आर्थिक स्थायित्व एवं वैश्विक आर्थिक सुधार का समर्थन

10. ठोस, सतत एवं संतुलित विकास अभी भी जी-20 के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है क्योंकि इसी से नौकरियों का सृजन होगा और पूरे विश्व में लोगों का हित कल्याण सुनिश्चित होगा। हम मांग की प्रक्रिया को मजबूत बनाने, वैश्विक विकास का समर्थन करने, भरोसा बहाल करने, लघु एवं मध्यम अवधि के जोखिमों का निराकरण करने, नौकरियों का सृजन करने तथा बेरोजगारी में कमी लाने के लिए सभी आवश्यक नीतिगत उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जैसा कि लॉस काबोस विकास एवं नौकरी कार्य योजना (अनुबंध देखें) में प्रतिबिम्बित हुई है। हम अपनी सभी प्रतिबद्धताओं का समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन करेंगे और इनके कार्यान्वयन पर नज़र रखेंगे।

11. बाज़ार से उत्पन्न नए दबावों की पृष्ठभूमि में यूरो क्षेत्र के जी-20 सदस्य अपने क्षेत्र की अखंडता एवं स्थिरता को संरक्षित रखने, वित्तीय बाज़ारों के कार्यकरण में सुधार लाने और संप्रभुओं एवं बैंकों के बीच सूचना सामग्रियों के आभाव को समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे। हम ठोस, सतत और संतुलित विकास हेतु जी-20 रूप रेखा के योगदान के रूप में विकास का समर्थन करने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने तथा राजकोषीय ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए यूरो क्षेत्र द्वारा पिछले शिखर

सम्मेलन के बाद से किए गए कार्यों का स्वागत करते हैं। इस संदर्भ में हम बैंकिंग प्रणाली में पूंजी का प्रवाह देने संबंधी स्पेन की योजना और स्पेन के वित्तीय पुनर्गठन प्राधिकरण का समर्थन करने की यूरो ग्रुप की घोषणा का स्वागत करते हैं। राजकोषीय कॉम्पैक्ट और इसका सतत कार्यान्वयन तथा विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ और ढांचागत सुधार एवं वित्तीय स्थायित्व के उपाय बेहतर राजकोषीय एवं आर्थिक एकीकरण के महत्वपूर्ण उपाय हैं जिनसे सतत ऋण लागतों को बढ़ावा मिलेगा। यूरोपीय स्थायित्व तंत्र की भावी स्थापना यूरोपीय सुरोक्षोपाय के संवर्धन का महत्वपूर्ण तंत्र है। हम आर्थिक एवं मौद्रिक संघ का कार्य पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने में यूरो क्षेत्र के कार्यों का समर्थन करते हैं। इस प्रयोजनार्थ हम समेकित वित्तीय रूप रेखा, समवेशी बैंकिंग पर्यवेक्षण, संकल्प तथा पूंजी प्रवाह एवं जमा बीमा की दिशा में ठोस उपायों पर विचार करने की मंशा का समर्थन करते हैं। यूरो क्षेत्र के सदस्य घाटे वाले देशों में प्रतिस्पर्धा और आधिक्य वाले देशों में मांग एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए ढांचागत सुधारों के जरिये अंतर यूरोपीय क्षेत्र समायोजन को बढ़ावा देंगे। यूरोपीय संघ के जी-20 सदस्य देश यूरोपीय एकल बाज़ार का कार्य पूरा करने और यूरोपीय निवेश बैंक, पायलट परियोजना बॉन्ड, ढांचा एवं सामंजस्य कोष जैसे यूरोपीय वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए निवेश, विकास एवं प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए वचनबद्ध हैं जबकि ढांचागत आधार पर आकलन किए जाने के लिए राजकोषीय मजबूती को कार्यान्वित करने की ठोस प्रतिबद्धता भी व्यक्त करते हैं। हम चाहते हैं कि यूरो क्षेत्र ग्रीस की अगली सरकार के साथ कम करते हुए यह सुनिश्चित करे कि वे यूरो क्षेत्र में सुधार और निरंतरता के मार्ग पर बने रहें।

12. जी-20 के सभी सदस्य देश वैश्विक विकास को सुदृढ़ बनाने तथा भरोसा बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ यह सुनिश्चित करेंगी कि राजकोषीय मजबूती की प्रक्रिया की गति आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त है जिसमें देश-विशेष परिस्थितियों का ध्यान रखा जाए और जिससे टोरंटो वचनवद्धताओं के अनुरूप लघु आवधिक राजकोषीय निरंतरता के बारे में उत्पन्न चिंताओं का समाधान किया जाए। जिन उन्नत एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं के पास राजकोषीय संसाधन हैं वे राष्ट्रीय परिस्थितियों एवं मांग की वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखकर स्वाभाविक रोजकोषीय स्थिरकों को कार्य करने देंगे। यदि आर्थिक स्थिति और खराब होती है तो पर्याप्त राजकोषीय संसाधन वाले देशों को आवश्यकता पड़ने पर घरेलू मांग के समर्थन में स्वतंत्र राजकोषीय उपायों को कार्यान्वित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अनेक देशों में शिक्षा, नवाचार एवं अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में उच्च निवेश से नौकरियों का सृजन हो सकता है तथा उत्पादकता एवं भावी विकास की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं। मांग और आर्थिक सुधार का समर्थन करने वाली विकासोन्मुख नीतियों की ज़रूरत को स्वीकार करते हुए संयुक्त राज्य अमरीका के संबंध में यह सुनिश्चित करते हुए वित्तीय मजबूती की गति का समन्वय

करेगा कि लोकवित्त को सतत दीर्घावधिक मार्ग पर रखा जाए जिससे कि वर्ष 2013 में राजकोषीय संकुचन से बचा जा सके।

13. मौद्रिक नीति से मध्यम अवधि तक मूल्यों में स्थिरता कायम रखी जा सकेगी जबकि आर्थिक सुधार को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा। हम अपने बैंकों में विश्वास को बढ़ावा देंगे और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की गतिशीलता को बढ़ाए रखेंगे जो मध्यम अवधि तक वित्तीय प्रणालियों को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है। हम ऋण माध्यमों को संरक्षित रखने तथा वैश्विक भुगतान एवं निपटान प्रणालियों की अखंडता बनाए रखने के लिए भी उपयुक्त उपाय करेंगे। ऋण देने की क्षमता वाले मजबूत बैंक भी वैश्विक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

14. जी-20 के सदस्य देश तेल के मूल्यों के विकास पर नज़र रखेंगे और ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त उपाय करने के लिए तैयार रहेंगे। इन उपायों में तेल उत्पादक देशों से मांग के अनुरूप ही आपूर्ति का स्तर बनाए रखेंगे। हम आवश्यकता पड़ने पर सऊदी अरब द्वारा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की इच्छा का स्वागत करते हैं। हम अन्य पण्यों के मूल्य के संबंध में भी सजग रहेंगे।

15. अनेक उभरते बाज़ारों में भी इस समय मंदी देखी जा रही है। इसके प्रत्युत्तर में ये देश विकास को बढ़ावा देने के लिए मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों को उपयुक्त दिशा दे रहें हैं जबकि वे स्थिरता भी सुनिश्चित कर रहें है। कुछ मामलों में ये देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए कमजोर विदेशी मांग के संदर्भ में घरेलू मांग को बढ़ावा देकर नए उपाय भी कर रहे हैं।

16. जिन देशों में चालू खाते का विशाल आधिक्य है उनके द्वारा घरेलू मांग में वृद्धि के प्रयासों का और जिन देशों में चालू खाता घाटा है उनमें राष्ट्रीय बचत में वृद्धि किए जाने का स्वागत करते हैं। उभरती आधिक्य अर्थव्यवस्थाएँ घरेलू खपत में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त कार्रवाई करेगी जिसमें मूल्य एवं कर विकृत्तियों को समाप्त किया जाना तथा सामाजिक सुरक्षा जाल का संवर्धन करना शामिल है जबकि आधिक्य वाली विकसित अर्थव्यवस्थाएँ और अपेक्षाकृत कमजोर निजी मांग वाले देश घरेलू मांग को बढ़ावा देंगे। ये कार्य सेवा क्षेत्र के उदारीकरण तथा निवेश को बढ़ावा देकर किया जा सकता है। चालू खाते घाटे वाले देशों में उच्च राष्ट्रीय बचत से वैश्विक असंतुलनों को कम करने में स्थायी योगदान मिलेगा। हम चालू खाता आधिक्य के संदर्भ में वृहत पण्य निर्यातकों की विशेष परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं। हम बाज़ार आधारित विनिमय दर प्रणालियों एवं विनिमय दर लोचनीयता की दिशा में और तेज़ी से आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं ताकि अंतर्निहित मौलिक तत्वों को प्रतिबिम्बित किया जाए, विनिमय दर की विसंगतियों से बचा जाए और विभिन्न मुद्राओं के प्रतिस्पर्धी मूल्यांकन से भी बचा जाए। हम रेमनिम्बी (आरएमबी) में गतिशीलता निर्धारित करने में बाज़ार तत्वों को अनुमति प्रदान करने की चीन

की वचनबद्धता का स्वागत करते हैं साथ ही हम विनिमय दर व्यवस्था में सुधार लाना चाहते है और विनिमय दर पारदर्शिता बढ़ाना चाहते हैं।

17. जी-20 के सभी देशों ने वैश्विक मांग को संवर्धित एवं अनुरक्षित रखने, नौकरियों के सृजन को बढ़ावा देने, वैश्विक पुनर्संतुलन में योगदान देने तथा विकास की क्षमता में वृद्धि करने के लिए ढांचागत सुधार की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए उत्पाद बाज़ार सुधार, आवासन क्षेत्र में स्थिरता लाने के उपाय, प्रतिस्पर्धा तथा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए श्रम बाज़ार सुधार और सामाजिक सुरक्षा जाल को सुदृढ़ बनाने के उपाय शामिल हैं। यह कार्य इस प्रकार किया जाएगा जिसमें राजकोषीय ज़िम्मेदारी हो, जिसमें उत्पादकता बढ़ाने के लिए कर सुधारों को आगे बढ़ाया जाए और विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुरूप हरित विकास तथा सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके। हम वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों से उन तौर तरीको का पता लगाने के लिए कहते हैं जिनके जरिये जी-20 अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दे सके तथा बहुपक्षीय विकास बैंकों के वित्तीय एवं तकनीकी समर्थन सहित अवसंरचना परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित किया जा सके।

18. सभी नीतिगत क्षेत्रों में हम घरेलू परियोजनों के लिए कार्यान्वित नीतियों के नकारात्मक प्रभावों को अन्य देशों के लिए कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। हम एक सुदृढ़ एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में अपने साझे हित की पुष्टि करते हैं। पूंजीगत प्रवाह प्राप्तकर्ता अर्थव्यवस्थों के लिए लाभकारी हो सकते हैं परंतु हम दोहराते हैं कि वित्तीय प्रभावों की अत्यधिक संवेदनशीलता और विनिमय दर का अव्यवस्थित उतार-चढ़ाव आर्थिक एवं वित्तीय स्थायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

19. विश्वसनीयता एवं भरोसा बढ़ाने में पारदर्शिता तथा ज़िम्मेदारी के महत्व को स्वीकार करते हुए हमने लॉस काबोस दायित्व आकलन रूपरेखा पर अपनी सहमति व्यक्त की है जो विकास एवं नौकरी कार्य योजना के साथ संलग्न है। यह रूपरेखा उन प्रक्रियाओं को स्थापित करती है जिनका हम अपनी नीतिगत प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन में प्रगति पर रिपोर्ट देने के लिए उपयोग करेंगे। हम इस नयी रूपरेखा के अंतर्गत पहले दायित्व रिपोर्ट का स्वागत करते हैं। हम अपने वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों को वर्ष 2013 में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाले नेताओं के शिखर सम्मेलन हेतु द्वितीय दायित्व रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य भी सौंपते हैं।

रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा

20. गुणवत्ता आधारित रोजगार हमारी वृहत आर्थिक नीतियों के केंद्र में है। श्रम अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा कवरेज तथा अच्छी आय वाली नौकरियों से सतत विकास में योगदान मिलता है, सामाजिक समावेश को बढ़ावा मिलता है और गरीबी घटती है। अतः हम उपयुक्त श्रम बाज़ार उपायों और अच्छे

कार्यों एवं नौकरियों के सृजन, विशेषकर युवा एवं अन्य कमजोर समूहों के लिए जिन पर आर्थिक संकट का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, के जरिये बेरोजगारी की समस्या का तत्काल समाधान करने हेतु अपने श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की अनुशंसाओं का समर्थन करते हैं। हम युवाओं को अच्छी नौकरियाँ दिलाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं जिनसे उनके जीवन की संभावनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। हम रोजगार पर जी-20 कार्यबल के कार्यों का स्वागत करते हैं और मंत्रियों द्वारा प्रस्तावित किए गए अनुसार इसके अधिदेश को एक और वर्ष के लिए बढ़ाए जाने का स्वागत करते हैं। लॉस काबोस विकास एवं नौकरी कार्य योजना के अनुरूप हम मानते हैं कि मौलिक सिद्धांतों एवं काम के अधिकार का पूर्ण सम्मान करते हुए हम ढांचागत सुधारों पर विचार कर सकते हैं जो श्रम बाजारों में अवसरों को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम शिक्षा, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण नीतियों जिनमें इंटर्नशिप और सेवकालीन परीक्षण शामिल है, में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं जिससे स्कूल से नौकरी तक के सफर के परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा।

21. विशेषकर युवाओं और आर्थिक संकट से प्रभावित अन्य लोगों के लिए नौकरियाँ उपलब्ध करना तथा बेरोजगारी दर में कमी लाना हम सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण है। हम जी-20 देशों में नौकरियों तथा जीवन स्तर को बढ़ावा देने पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की रिपोर्ट का स्वागत करते हैं। हम नौकरियों को दोबारा वापस पाने तथा बेरोजगारी दर में कमी लाने की गति में तेज़ी लाने से संबन्धित उपायों पर बल देना जारी रखेंगे।

22. हम राष्ट्रीय दर पर निर्धारित सामाजिक सुरक्षा तंत्रों की स्थापना किए जाने के महत्व को स्वीकार करते हैं। हम अंतर-एजेंसी तथा अंतर्राष्ट्रीय नीति, सामंजस्य, सहयोग तथा ज्ञान के बँटवारे की प्रक्रिया को बढ़ावा देना जारी रखेंगे जिससे कि अल्प आय वाले देशों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित सामाजिक सुरक्षा तंत्रों के कार्यान्वयन हेतु क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान की जा सके। हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अल्प आय वाले देशों के संदर्भ में नीतिगत विकल्प की पहचान करने के लिए भी कहते हैं कि प्रभावी सतत सुरक्षा तंत्रों का किस प्रकार विकास किया जाए।

23. हम जी-20 सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की पूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक भागीदारी के समक्ष उत्पन्न बाधाओं को दूर करने तथा उनके लिए आर्थिक अवसरों का विस्तार करने की दिशा में ठोस कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। हम कौशल प्रशिक्षण, मजदूरी एवं वेतन, कार्यस्थल पर व्यवहार तथा देखभाल की ज़िम्मेदारी सहित सभी क्षेत्रों में महिला-पुरुष समानता को बढ़ावा देने के लिए अपनी ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं।

24. हम अपने श्रम मंत्रियों से इस कार्यसूची के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा करने का अनुरोध भी करते हैं और सामाजिक भागीदारों के साथ विचार विमर्श करने की प्रक्रिया का स्वागत करते हैं। इस संबंध में हम मेक्सिको की अध्यक्षता में जी-20 की प्रक्रिया के अंतर्गत बिजनेस-20 (बी-20), लेबर-20 (एल-20) के योगदानों की सराहना करते हैं।

25. हम नौकरियों का सृजन करने तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के वाहन के रूप में यात्रा एवं पर्यटन की भूमिका को स्वीकार करते हैं जबकि विदेशी राष्ट्रिकों के प्रवेश को नियंत्रित करने संबंधी देशों के संप्रभु अधिकारों को भी स्वीकार करते हैं। हम नौकरियों और अच्छे कार्यों के सृजन, गरीबी उन्मूलन तथा वैश्विक विकास के समर्थन में यात्रा सरलीकरण पहलकदमियों की दिशा में कार्य करेंगे।

व्यापार

26. हम व्यापार और निवेश को मुक्त बनाने, बाज़ारों का विस्तार करने आर सभी प्रकार के संरक्षणवाद का प्रतिरोध करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। ये बातें सतत वैश्विक आर्थिक सुधार, नौकरियों एवं विकास के लिए अनिवार्य शर्तें हैं। हम एक मुक्त, पूर्वानुमेय, विधिसम्मत, पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के महत्व को रेखांकित करते हैं और विश्व व्यापार संगठन की प्रमुखता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

27. आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए निवेश के महत्व को स्वीकार करते हुए हम निवेशकों के लिए अनुकूल व्यावसायिक परिवेश बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं।

28. हम विश्व में लगातार मिल रहे संरक्षणवाद के उदाहरणों पर भी गंभीर रूप से चिंतित हैं। कान में हमारे द्वारा व्यक्त प्रतिबद्धता के अनुरूप हम व्यापार और निवेश को प्रभावित करने वाले उपायों के संदर्भ में वर्ष 2014 के अंत तक अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। इसके साथ ही हम नए निर्यात नियंत्रणों तथा विश्व व्यापार संगठन के प्रतिकूल उपायों सहित नए संरक्षणवादी उपायों को वापस लेने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त करते हैं जिससे निर्यात को बढ़ावा मिल सके। हम व्यापार और निवेश उपायों पर विश्व व्यापार संगठन तथा व्यापार एवं विकास से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नए एवं अनुवीक्षण संबंधी कार्यों की सराहना करते हैं तथा उन्हे अपने-अपने अधिदेशों के अनुरूप इन क्षेत्रों में कार्यों को संवर्धित तथा गहन बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

29. हम विश्व व्यापार के लिए क्षेत्रीय एवं वैश्विक मूल्य शृंखलाओं की प्रासंगिकता पर प्यूर्टो बलार्टा में हमारे व्यापार मंत्रियों के बीच हुई चर्चा, जिसमें आर्थिक प्रगति, रोजगार एवं विकास को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका को स्वीकार किया गया और इस प्रकार की मूल्य शृंखलाओं में विकासशील देशों की

भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया, को मूल्यवान मानते हैं। हम विश्व व्यापार संगठन (डबल्यूटीओ), अंकटाड तथा ओईसीडी के अधिदेशों के अंतर्गत इन चर्चाओं को गहन बनाने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के कार्यकरण तथा व्यापार एवं निवेश प्रवाहों, विकास एवं नौकरियों के साथ उनके सम्बन्धों का विश्लेषण करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने और व्यापार प्रवाहों को मापने का आह्वान करते हैं जिससे कि इस बात को बेहतर तरीके से समझा जा सके कि हमारी कार्रवाइयाँ किस प्रकार हमारे देशों एवं अन्य को प्रभावित करती हैं। इसकी प्रगति की रिपोर्ट रूस के अध्यक्षता काल में सौंपी जाएगी।

30. कान विज्ञप्ति के अनुसरण में हम दोहा विकास कार्यसूची अधिदेश के साथ हैं तथा स्पष्ट तरीके से व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। हम दोहा दौर की वार्ताओं के समापन की दिशा में कार्य करना जारी रखेंगे जिसमें वे विशेष क्षेत्र शामिल हैं जैसे कि व्यापार सरलीकरण तथा अल्पविकसित देशों से जुड़े अन्य मुद्दे। हम विश्व के गरीब देशों के लिए विश्व व्यापार संगठन की अधिमिलन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाने नें प्रगति करने का आह्वान करते हैं।

31. हम विश्व व्यापार संगठन के नियमित कार्यों को सम्पन्न करने और विवाद-निपटान प्रणाली के तौर-तरीकों को सुदृढ़ बनाने का समर्थन करते हैं। हम अपने-अपने प्रतिनिधियों को इस एकीकृत अर्थव्यवस्था में बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की चुनौतियों एवं अवसरों पर और चर्चा करने का निर्देश भी देते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे का संवर्धन करना

32. हम प्रभावी वैश्विक एवं क्षेत्रीय सुरक्षा के जालों के महत्व को स्वीकार करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। यह एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहकारी प्रयास का परिणाम है जिसमें अनेक देश शामिल हैं। इसमें 450 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक राशि की प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी है जो वर्ष 2010 के सुधार के अंतर्गत कोटे में की गयी वृद्धि के अतिरिक्त है। ये संसाधन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होंगे और किसी विशेष क्षेत्र के लिए निर्धारित नहीं होंगे। संरक्षित परिसंपत्तियों के रूप में निर्धारित इन संसाधनों को द्विपक्षीय ऋण एवं निवेश माध्यमों से प्रदान किया जाएगा जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदित तौर-तरीकों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामान संसाधन लेखे से सम्बद्ध नोट क्रय करार। यह प्रयास वैश्विक वित्तीय स्थायित्व को संरक्षित रखने और संकट के रोकथाम एवं समाधान करने में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका के संवर्धन की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

33. हम 2012 की अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष/ विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों की निर्धारित तारीख तक 2010 कोटा और अभिशासन सुधार को कार्यान्वित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। ये सुधार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वैधता, प्रासंगिकता तथा प्रभाविता का उन्नयन करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं और कोष की निगरानी प्रणाली को संवर्धित करने तथा यह सुनिश्चित करने के प्रयासों का समर्थन करेंगे कि उपयुक्त भूमिका निभाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास पर्याप्त संसाधन मौजूद हों। इन सुधारों के भाग के रूप में हम कोटा फार्मूले की व्यापक समीक्षा का कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि जनवरी 2013 तक वर्तमान कोटा फार्मूले की कमियों और कमजोरियों को दूर किया जा सके और जनवरी 2012 तक कोटे की अगली सामान्य समीक्षा का कार्य पूरा हो सके। हम इस बात पर सहमत हैं कि उक्त फार्मूला सरल और पारदर्शी तथा कोटे की विभिन्न भूमिकाओं के अनुरूप हो। हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि फार्मूले पर आधारित कोटे का वितरण इस प्रकार हो कि इससे विश्व अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की सापेक्षित ताकत प्रतिबिम्बित हो क्योंकि गतिशील उदीयमान बाज़ारों एवं विकासशील देशों में सकल घरेलू उत्पाद में हुई ठोस वृद्धि के कारण इसमें व्यापक परिवर्तन आ गया है। हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गरीब सदस्यों के विचारों एवं प्रतिनिधित्व के महत्व की पुष्टि करते हैं। हम अपने वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों से नवंबर में होने वाली उनकी बैठक के दौरान इस मुद्दे पर हुई प्रगति की समीक्षा करने का अनुरोध करते हैं।

34. हम इस बात पर सहमत हुए कि वर्तमान निगरानी रूपरेखा का महत्वपूर्ण संवर्धन किया जाना चाहिए और इसमें वैश्विक, घरेलू तथा वित्तीय स्थायित्व पर बल देते हुए द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय निगरानी प्रणाली के बेहतर समेकन का उपयोग किया जाना चाहिए। हम प्रस्तावित एकीकृत निगरानी निर्णय के लिए विभिन्न विचारों को आगे बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य का स्वागत करते हैं और निर्णय प्रक्रिया का समर्थन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। हम विनिमय दर नीतियों पर कठोर निगरानी के महत्व पर बल देते हैं तथा निगरानी गतिविधियों के पर्याप्त कवरेज का समर्थन करते हैं। इसमें वैश्विक तरलता, पूंजी प्रवाह, पूंजी लेखा उपाय, मुद्रा एवं राजकोषीय, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र की नीतियाँ शामिल हैं जिनका प्रभाव बाह्य स्थायित्व पर पड़ सकता है। हम बाह्य क्षेत्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किए जा रहे कार्यों का स्वागत करते हैं जिससे बहुपक्षीय विश्लेषण सुदृढ़ होगा तथा निगरानी की पारदर्शिता में वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी को सुविधाजनक बनाने में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति (आईएमएफ़सी) की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष /विश्व बैंक की अगली वार्षिक बैठकों में होने वाली ठोस प्रगति की प्रतीक्षा है।

35. हम अन्तरिम प्रगति रिपोर्ट का स्वागत करते हैं और हमें संयुक्त वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ताकि विश्व बैंक, क्षेत्रीय विकास बैंको, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़), ओईसीडी और अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) द्वारा तैयार किए जाने वाले स्थानीय मुद्रा बॉन्ड बाज़ारों के विकास का समर्थन किया जा सके। इसकी पूर्ण रिपोर्ट जी-20 के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की नवंबर में आयोजित होने वाली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। यह मुद्दा उभरते बाज़ारों एवं विकासशील देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जा रहा है कि इन बाज़ारों की तरलता, प्राभविता एवं प्रचालन को वर्तमान वैश्विक वित्तीय स्थिति द्वारा चुनौती मिल रही है।

वित्तीय क्षेत्र में सुधार तथा वित्तीय समावेश को बढ़ावा

36. हम वित्तीय स्थायित्व को सुदृढ़ बनाए के लिए जी-20 की प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने पर वित्तीय स्थिरता बोर्ड की प्रगति रिपोर्ट एवं राष्ट्रीय स्तर पर एफ़एसबी के संवर्धित कार्यान्वयन निगरानी का स्वागत करते हैं। हम सहमत नीतियों के समयबद्ध पूर्ण एवं सतत कार्यान्वयन के प्रति वचनबद्ध हैं ताकि एक स्थायी और समेकित वैश्विक वित्तीय प्रणाली का समर्थन किया जाए और भावी संकटों की रोकथाम की जा सके।

37. हम अपनी सभी वित्तीय सुधार अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने में हुई प्रगति का रिकॉर्ड रखने के लिए ट्रैफिक लाइट स्कोर बोर्ड प्रकाशित किए जाने का स्वागत करते हैं और उन सभी क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए सभी प्रकार की आवश्यक कार्रवाई करने का वचन देते हैं जिनमें नीतिगत विकास अथवा कार्यान्वयन संबंधी कठिनाइयों की पहचान की गयी है।

38. विशेषकर हम कार्यान्वयन मानीटरन के लिए एफ़एसबी की समन्वय रूपरेखा (सीएफ़आईएम): वेसल पूंजी और तरलता रूपरेखा; विश्व स्तर पर क्रमिक रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान रूप रेखा (जीएसआईएफ़आई) समाधान व्यवस्था; शैडो बैंकिंग और मुआवजा प्रथाओं द्वारा चिह्नित प्राथमिक सुधार क्षेत्रों में हुई ठोस प्रगति का स्वागत करते हैं। हम सुधारो का पूर्ण कार्यान्वयन प्राप्त करने के लिए इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य पूरा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं।

39. हम अपनी इस प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं कि सभी मानक ओटीसी डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में आदान-प्रदान अथवा इलेक्ट्रोनिक व्यापार मंचों के जरिये व्यापार होना चाहिए जिसे वर्ष 2012 के अंत तक समकक्ष पक्षों द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं की रिपोर्ट व्यापार रेपोसितारी में की जानी चाहिए तथा अलग-अलग अनुमोदित संविदाएँ उच्च पूंजी अनिवार्यताओं के अध्यधीन होनी चाहिए। हम कार्यान्वयन पर एफ़एसबी की प्रगति रिपोर्ट का स्वागत करते हैं। आज जब केंद्रीय अनुमोदन के लिए एक लोचनीय तथा प्रभावी वैश्विक रूपरेखा के लिए चार सुरक्षोपाय के संदर्भ में

ठोस प्रगति हुई है तो न्याय क्षेत्रों को अपनी नीति निर्णय प्रक्रिया को शीघ्र अंतिम रूप देना चाहिए और केंद्रीय अनुमोदन के लिए जी-20 की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु आवश्यक विधान और विनियम बनाने चाहिए। हम अलग-अलग अनुमोदित डेरिवेटिव के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मानकों के अनुरूप प्रमुख सिद्धांतों का विकास करने में हुई प्रगति को स्वीकार करते हैं और इस वर्ष के अंत तक प्रस्तावित वैश्विक मानक को अंतिम रूप देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारकों को प्रोत्साहित करते हैं ताकि अन्य ओटीसी डेरिवेटिव सुधारों और वेसल पूंजी रूप रेखा के लिए कार्यान्वयन समय सीमा का अनुपालन किया जाए।

40. हम वेसल 2, 2.5 तथा 3 के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं और न्याय क्षेत्रों से सहमत समय सीमा के अनुरूप मानकों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने का आह्वान करते हैं। हम बाज़ार जोखिम रूपरेखा की मौलिक सुरक्षा करने के लिए वेसल समिति की परामर्शी प्रस्तावों का स्वागत करते हैं। हम ठोस मुआवजा प्रस्तावों के लिए सिद्धांतों एवं मानकों के कार्यान्वयन में हुई एफ़एसबी की प्रगति रिपोर्ट का स्वागत करते हैं तथा यह सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता कीपुष्टि करते हैं कि इनका अनुपालन किया जाए और एफ़एसबी से इसका मानिटरन जारी रखने का अनुरोध करते हैं।

41. हम अपनी राष्ट्रीय संकल्प व्यवस्थाओं को एफ़एसबी की प्रभावी संकल्प व्यवस्थाओं के अनुरूप बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं ताकि कोई बैंक और अन्य वित्तीय संस्था असफल होती है तो इसका बहुत अधिक प्रभाव न पड़े। इस प्रयोजनार्थ हम सभी जी-एसआईएफ़आई के लिए सुधार एवं संकल्प योजनाओं तथा संस्था विशेष सहयोग करारों का समर्थन करते हैं। हम एसआईएफ़आई के पर्यवेक्षण की गहनता एवं प्रभाविता को सुदृढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं और एसआईएफ़आई से अनुरोध करते हैं कि वे नवम्बर 2012 में आयोजित होने वाली जी-20 वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में इससे संबन्धित प्रगति रिपोर्ट सौंपे।

42. हम घरेलू स्तर पर महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) संबन्धित नीतिगत उपायों की पहचान करने के लिए साझी रूपरेखा के कुछ सिद्धांतो का विकास करने में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं और अपने वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों से नवम्बर में आयोजित होने वाली उनकी बैठक में इन अनुशंसाओं की समीक्षा करने का अनुरोध करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) के साथ परामर्श करके एफ़एसबी से अप्रैल 2013 तक विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण बीमा कर्ताओं के लिए नीतिगत उपायों की पहचान करने का कार्य पूरा करने का अनुरोध करते हैं। क्रमिक जोखिमों में कमी लाने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन आयोग (आईओएससीओ) के परामर्श से एफ़एसबी द्वारा की गयी तैयारियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि वर्ष 2012 के अंत तक महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय इकाइयों की पहचान की जा सके। हम भुगतान एवं निपटान प्रणाली समिति (सीपीएसएस) और आईओएससीओ से

महत्वपूर्ण बाज़ार अवसंरचनाओं पर कार्य जारी रखने का अनुरोध करते हैं। हम आईएआईएस से वर्ष 2013 के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बीमा समूहों के पर्यवेक्षण हेतु साझी रूपरेखा का विकास करने का कार्य जारी रखने का अनुरोध करते हैं।

43. हम क्रेडिट रेटिंग के संबंध में यांत्रिक विश्वसनीयता को समाप्त करने में राष्ट्रीय प्राधिकरणों में तथा मानक निर्धारण निकायों द्वारा त्वरित प्रगति करने का आह्वान करते हैं जिससे क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बीच प्रतिस्पर्धा की पारदर्शिता में वृद्धि होगी। हम उच्च गुणवत्ता आधारित लेखा मानकों पर सर्वसम्मति बनाने के लिए भी किए जा रहे कार्यों को अपना समर्थन प्रदान करते हैं। हम क्रेडिट डिफ़ाल्ट अदला-बदली बाज़ारों के कार्यकरण पर आईओएससीओ की रिपोर्ट का स्वागत करते हैं और आईओएससीओ से नवम्बर 2012 में आयोजित होने वाली वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में रिपोर्ट करने का अनुरोध करते हैं।

44. हम लोक हित का प्रतिनिध्तिव करने वाले वैश्विक अभिशासन रूपरेखा के साथ वित्तीय कारोबार के पक्षकारों के लिए एक वैश्विक विधिक इकाई पहचान कर्ता (एलईआई) प्रणाली के विकास किए जाने के लिए एफ़एसबी की सिफ़ारिशों का समर्थन करते हैं। एलईआई प्रणाली का शुभारंभ मार्च 2013 में किया जाएगा और हम एफ़एसबी से नवम्बर 2012 में आयोजित होने वाली वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में रिपोर्ट करने का अनुरोध करते हैं। हम एलईआई को वैश्विक रूप से स्वीकार किए जाने को प्रोत्साहित करते हैं ताकि बाज़ार जोखिमों की पहचान और प्रबंधन में प्राधिकरणों तथा बाज़ार भागीदारों का समर्थन किया जा सके।

45. हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के समन्वय से तैयार एफ़एसबी अध्ययन का स्वागत करते हैं जिसके जरिये उभरते बाज़ारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) के लिए सहमत वित्तीय नियामक सुधारों के संभावित परिणामों की पहचान की जा सके। हम एफ़एसबी द्वारा जारी विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग तथा एफ़एसबी, मानक निर्धारकों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं एवं ईएमडीई के राष्ट्रीय प्राधिकरणों के बीच संवाद को बढ़ावा देते हैं जिसका उद्देश्य सहमत सुधारों को कार्यान्वित करने की प्रतिबद्धता के बिना ही उपयुक्त तरीके से विभिन्न समस्याओं का समाधान करना है।

46. हम एफ़एसबी को एक स्थायी संगठनात्मक मंच पर स्थापित करने के लिए संशोधित एफ़एसबी चार्टर की अनुशंसाओं का समर्थन करते हैं जिसमें विधिक हस्तियों, मजबूत अभिशासन, बेहतर वित्तीय स्वायत्तता और संवर्धित क्षमता का सहारा लेकर वित्तीय नियामक नीतियों के विकास और कार्यान्वयन का समन्वय किया जाए तथा बीआईएस के साथ ठोस संबंध कायम रखे जाए। हम अपनी अगली बैठक तक इन अनुशंसाओं और नवम्बर 2012 में आयोजित होने वाली वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के

गवर्नरों की बैठक तक इसमें ठोस प्रगति करना चाहते हैं। हम एफ़एसबी से इसके प्रतिनिधित्व की रूपरेखा की समीक्षा जारी रखने का आह्वान करते हैं।

47. हम पर्यवेक्षण एवं नियामक सूचना के आदान प्रदान एवं सहयोग मानदंडों का अनुपालन करते हुए एफ़एसबी द्वारा किए जा रहे कार्यों का स्वागत करते हैं और नवम्बर 2012 में आयोजित होने वाली वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक से पूर्व इस संबंध में हुई प्रगति पर सार्वजनिक वक्तव्य चाहते हैं।

48. जहां तक कर क्षेत्र का संबंध है, हम पारदर्शिता बढ़ाने और सूचना के व्यापक आदान-प्रदान की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। हम विश्व मंच की रिपोर्ट के अनुसार हुई प्रगति की सराहना करते हैं और सभी देशों से मानकों का पूर्ण अनुपालन करने तथा समीक्षा, विशेषकर 13 न्याय क्षेत्रों, जिनकी रूपरेखा के अंतर्गत उन्हें अभी चरण 2 के लिए अनुमति नहीं मिली है, की अवधि के दौरान निर्धारित अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने का अनुरोध करते हैं। हम विश्व मंच से सूचना का आदान-प्रदान किए जाने से संबन्धित प्रथाओं की प्रभाविता की जांच करने और हमें तथा वित्त मंत्रियों को इसकी सूचना देने का अनुरोध करते हैं। हम स्वतः सूचना आदान-प्रदान की प्रथा पर ओईसीडी की रिपोर्ट का स्वागत करते हैं जिसमें हम इस प्रथा को कार्यान्वित करने का उदाहरण पेश करना चाहते हैं। हम विभिन्न देशों से यथा-उपयुक्त इस विकसित प्रथा में शामिल होने का आह्वान करते हैं और सभी न्यायक्षेत्रों से पारस्परिक प्रशासनिक सहायता से सम्बद्ध बहुपक्षीय अभिसमय पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध करते हैं। हम ओसलो संवाद की रोम बैठक के परिणामों सहित गैरकानूनी प्रवाहों की समस्या का मुक़ाबला करने हेतु विभिन्न एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाए जाने के प्रयासों का भी स्वागत करते हैं। हम विश्वास की कमी तथा लाभ के स्थानांतरण को रोकने की आवश्यकता भी दोहरते हैं और हम इस क्षेत्र में ओईसीडी के जारी कार्यों पर यथोचित ध्यान देते रहेंगे।

49. हम वित्तीय कार्यबल (एफ़एटीएफ़) अधिदेश को नवीकृत किए जाने का समर्थन करते हैं जिससे धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषन तथा सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रसार रोकने के लिए किए जा रहे वैश्विक प्रयासों में मदद मिलेगी। जी-20 के सदस्य देश संशोधित एफ़एटीएफ़ को अंगीकार किए जाने का भी स्वागत करते हैं और इन्हें इनका कार्यान्वयन किए जाने की प्रतीक्षा है। हम सामरिक धन शोधन रोधी/ आतंकवाद-रोधी वित्त पोषण (एएमएल/सीएफ़टी) की कमियों के साथ उच्च जोखिम वाले न्याय क्षेत्रों की निगरानी में एफ़एटीएफ़ द्वारा की गयी प्रगति का स्वागत करते हैं। हम भ्रष्टाचार का मुक़ाबला करने, कॉर्पोरेट माध्यमों में पारदर्शिता बढ़ाने और कर अपराधों के विरुद्ध सहयोग करने, तथा एएमएल/सीएफ़टी की प्रभाविता बढ़ाने का भी स्वागत करते हैं। हमें पारस्परिक मूल्यांकनों के अगले दौर

के लिए एफ़एटीएफ़ आकलन प्रक्रिया को अद्यतन बनाए जाने का कार्य वर्ष 2013 तक पूरा किए जाने की प्रतीक्षा है।

50. हम वर्ष 2011 की रिपोर्ट में वित्तीय समावेश से सम्बद्ध वैश्विक भागीदारी (जीपीएफ़आई) द्वारा की गयी पाँच अनुशंसाओं पर हुई प्रगति का स्वागत करते हैं और जीपीएफ़आई से इसका पूर्ण कार्यान्वयन करने की दिशा में प्रयास जारी रखने का अनुरोध करते हैं। हम जीपीएफ़आई द्वारा विकसित वित्तीय समावेश संकेतकों के जी-20 बुनियादी सेट का समर्थन करते हैं। आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन में लघु एवं मध्यम उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए हम एसएमई वित्त कॉम्पैक्ट की शुरुआत किए जाने का स्वागत करते हैं जो नए माडलों का विकास करने के प्रयासों और एसएमई वित्त पोषण के संबंध में विकासशील देशों के समक्ष हम मानक निर्धारण निकायों में वित्तीय समावेश के संबंध में आगामी जीपीएफ़आई के कार्यों का स्वागत करते हैं जो एक समर्थकारी नियामक परिवेश के सृजन में सहायक होगा। हम जीपीएफ़आई से इस संबंध में नवम्बर 2012 में आयोजित होने वाली वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में इसकी प्रगति की रिपोर्ट देने का आह्वान करते हैं। अंततः हम चौथे जीपीएफ़आई समूह का सृजन करने के जारी प्रयासों का समर्थन करते हैं जिसके जरिये उपभोक्ता संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरता जैसे मुद्दों पर विशेष बल दिया जाएगा।

51. हम जी-20 वित्तीय समावेश समकक्ष शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय समन्वय मंचो एवं रणनीतियों के प्रति प्रतिबद्ध जी-20 देशों और गैर जी-20 देशों के प्रयासों को स्वीकार करते हैं तथा नए वित्तीय समावेश के लिए जी-20 सिद्धांतों के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहित करते हैं। इनमें माया घोषणा के अंतर्गत विकासशील और उभरते देशों द्वारा वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने की दिशा में की गयी ठोस प्रतिबद्धता भी शामिल है जिसमें विश्व बैंक समूह तथा वित्तीय समावेश संघ और संयुक्त राष्ट्र तथा द्विपक्षीय दाताओं सहित अन्य भागीदारों द्वारा समर्थन की दिशा में किए जा रहे प्रयास शामिल हैं।

52. वित्तीय शिक्षा के संदर्भ में हम ओईसीडी/वित्तीय शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क (आईएनएफ़ई) तथा वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों से सम्बद्ध उच्चस्तरीय सिद्धांतों का समर्थन करते हैं और ओईसीडी/आईएनएफ़ई तथा विश्व बैंक और जीपीएफ़आई को वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अतिरिक्त साधनों की सुपुर्दगी करने का अनुरोध करते हैं जिसकी रिपोर्ट अगले शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत की जाए। वित्तीय उपभोगता संरक्षण कार्यसूची को आगे बढ़ाने के संदर्भ में हम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय उपभोगता संरक्षण नेटवर्क (फिंकोनेट) पर हुई चर्चा को नोट करते हैं तथा औपचारिक रूपरेखा एवं वित्तीय समर्थन के मुद्दे पर सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम वित्तीय उपभोगता संरक्षण से सम्बद्ध उच्च स्तरीय सिद्धांतों के कार्यान्वयन को समर्थन प्रदान करने के लिए प्रभावी दृष्टिकोण

विकसित करने हेतु वित्तीय उपभोगता संरक्षण पर जी-20/ओईसीडी कार्यबल द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना का समर्थन करते हैं और हमे वर्ष 2013 में सेंट पीटर्सबर्ग में नेताओं के शिखर सम्मेलन में इसकी अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा है।

53. हम महिलाओं और युवाओं की वित्तीय सेवाओं एवं वित्तीय शिक्षा तक पहुँच स्थापित करने की आवश्यकता को समझते हैं और जीपीएफ़आई, ओईसीडी/आईएनएफ़ई एवं विश्व बैंक को उन बाधाओं की पहचान करने के लिए कहते हैं जो उनके समक्ष आ सकती हैं। हम अगले शिखर सम्मेलन तक एक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का भी आह्वान करते हैं।

54. हम मेक्सिको वित्तीय समावेश चुनौती: अबाध संपर्क के लिए नवाचार समाधान की शुरुआत किए जाने का स्वागत करते हैं जो बहुमूल्य, रियायती, सुरक्षित तथा व्यापक वित्तीय सेवाओं के सृजन के जरिये वित्तीय समावेश के समक्ष आने वाली बाधाओं का समाधान करता है।

खाद्य सुरक्षा का संवर्धन तथा पण्यों के मूल्य में उतार चढ़ाव की समस्या का समाधान

55. वर्ष 2011 में कृषि मंत्रियों द्वारा पारित खड़ी मूल्य उतार-चढ़ाव एवं कृषि से सम्बद्ध कार्य योजना में रेखांकित किया गया था कि वर्ष 2050 तक 9.3 बिलियन से अधिक जनसंख्या के लिए भोजन मुहैया करने के लिए कृषि उत्पाद में 50 से 70 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। विकासशील देशों में लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि कृषि शर्तों की विविधता पर विचार करते हुए सतत आधार पर उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना आज विश्व के सामने विद्यमान सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। सहेल तथा अफ्रीकी शृंग के संकट से इस बात का भी पता चलता है कि खाद्य असुरक्षा के प्रति आपातकालीन एवं दीर्घावधिक अनुक्रियाओं को संवर्धित करना एक तात्कालिक चुनौती बनी हुई है। हम यह भी नोट करते हैं कि कुपोषण किसी भी देश के मानव संसाधनों के लिए खतरनाक है और इसकलिए हम पोषण अभियानों को आगे बढ़ाने एवं इनमें जी-20 सदस्यों को व्यापक रूप से शामिल करने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं।

56. हम विकास से सम्बद्ध सिओल बहुवर्षीय कार्य योजना के खाद्य सुरक्षा स्तंभों को कार्यान्वित किए जाने में हुई पर्याप्त प्रगति का स्वागत करते हैं। हम कृषि उत्पादकता बढ़ाने, खाद्य एवं कृषि संगठन ओईसीडी द्वारा समन्वित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त सूचनाओं तथा जी-20 एवं सभ्य समाज की अनुशंसाओं पर हुई प्रगति के संबंध में हम जी-20 कृषि उपमंत्रियों की रिपोर्ट का समर्थन करते हैं।

57. भुखमरी का मुक़ाबला करने के लिए हम विषुवत रेखीय कृषि मंच, कृषि जोखिम प्रबंधन मंच, त्वरित अनुक्रिया मंच, क्षेत्रीय आपातकालीन खाद्य बल, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम तथा जिम्मेदार कृषि

निवेश के सिद्धांतो सहित अपनी अन्य पहलकदमियों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। खाद्य पदार्थों के मूल्य में उतार-चढ़ाव में कमी लाने के लिए वैश्विक पारदर्शिता के योगदान को स्वीकार करते हुए हम कृषि बाज़ार सूचना प्रणाली एएमआईएस के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की सरहना करते हैं। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि और भी स्थिर, पूर्वानुमेय, विकृति मुक्त, एवं पारदर्शी व्यापार प्रणाली, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

58. हम विश्व खाद्य कार्यक्रम (डबल्यूएफ़पी) द्वारा अवाणिज्यिक मानवीय परियोजनों से खरीदे जाने वाले खाद्य पदार्थों पर से आयात प्रतिबंध और असाधारण करों को हटाने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में भूमि, मात्स्यिकी तथा वनों के कार्यकाल के दायित्वपूर्ण अभिशासन पर स्वेच्छिक दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करते हैं।

59. हम कृषि क्षेत्र में बाज़ार की असफलताओं से बाधित नए कृषि उत्पादों और प्रणालियों के निजी क्षेत्र नवाचार को बढ़ावा देते हुए गरीब एवं कमजोर लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से "कृषि परिणाम" की शुरुआत किए जाने का स्वागत करते हैं। हमें पोषक फसलों, फसल कटाई के बाद कचरा प्रबंधन, भंडारण समाधान तथा फसल गुणवत्ता प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उप-सहारा अफ्रीका में नवाचरों पर केन्द्रित प्रयोगिक परियोजनाओं की शुरुआत करने की प्रतीक्षा है। हम उनकी भी सराहना करते हैं जिन्होने इस पहल के लिए धन उपलब्ध करने और इसमें व्यापक भागीदारी प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है अथवा इस प्रकार की मंशा के संकेत दिए हैं।

60. हम कृषि को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं और सतत तरीके से जल एवं मृदा उपयोग की प्रभाविता में सुधार को महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रयोजनार्थ हम उपलब्ध प्रौद्योगिकियों, जानी-पहचानी प्रथाओं तथा मृदा उपज संवर्धन और कृषि वानिकी जैसे तकनीकों के बेहतर उपयोग और विकास का समर्थन करते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से विज्ञान आधारित विकल्प पर एक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आह्वान करते हैं ताकि लघु कृषि सहित अन्य कृषि के लिए जल के उपयोग की प्रभाविता में सुधार लाया जा सके।

61. हम अंतर्राष्ट्रीय पण्य बाज़ारों में स्थायित्व कायम रखने में वैश्विक आर्थिक सुधार के महत्व को स्वीकार करते हैं। हम पारदर्शी भौतिक एवं वित्तीय पण्य बाज़ारों के कार्यकरण के महत्व पर बल देते हैं। हम पण्यों के मूल्य में भारी उतार-चढ़ाव की समस्या में भी कमी लाना चाहते हैं ताकि खाद्य सुरक्षा एवं समवेशी विकास को बढ़ावा मिल सके। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि पण्यों के मूल्य में भारी उतार-चढ़ाव का सभी देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इससे उन देशों के बजट और आर्थिक आयोजना की पूर्वानुमेयता में भी बाधा आती है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि पण्यों के मूल्य में

उतार-चढ़ाव के नकारात्मक प्रभावों को दूर करना गरीबी हटाने तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अतः हम विकास पर पण्यों को मूल्य में उतार-चढ़ाव के वृहत आर्थिक प्रभावों पर जी-20 रिपोर्ट का समर्थन करते हैं। इस प्रकार के प्रभावों का प्रशमन करने के लिए नीतिगत विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा अंक्टाड की भागीदारी तथा इनके महत्वपूर्ण योगदानों की भी सराहना करते हैं। हम रिपोर्ट में उल्लिखित कार्यों के अन्य संभावित क्षेत्रों को नोट करते हुए इन भौतिक बाज़ारों का बेहतर कार्यकरण सुविधाजनक बनाने के लिए जी-20 के योगदान के संबंध में वर्ष 2013 में रिपोर्ट देने के लिए अपने वित्त मंत्रियों से कहते हैं। हम पारदर्शिता बढ़ाने और वित्तीय पण्य बाज़ारों का दुरुपयोग रोकने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। इस प्रक्रिया में बाज़ार नियमकों एवं पर्यवेक्षण ढांचों का उपयोग किया जा सकता है। इस संबंध में हमें नवंबर 2012 तक पण्य बाज़ारों पर आईओएससीओ की रिपोर्ट का कार्यान्वयन किए जाने की प्रतीक्षा है।

62. हम स्वीकार करते हैं कि ऊर्जा पण्यों के मूल्य में उतार-चढ़ाव भी आर्थिक अस्थिरता का एक महत्वपूर्ण कारण है। हम सुव्यवस्थित और पारदर्शी ऊर्जा बाज़ारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम जेओडीआई-आयल की समयबद्धता, क्षमता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए कार्य करना जारी रखेंगे और हमें अगले वर्ष इसकी प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने की प्रतीक्षा है। इन्हीं सिद्धांतों पर हम जेओडीआई-गैस डेटाबेस पर भी कार्य करेंगे। हम जेओडीआई-आयल डेटाबेस की विश्वसनीयता में सुधार पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच (आईईएफ़) की रिपोर्ट की आशा कर रहे हैं। साथ ही हम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, आईईएफ़ तथा पेट्रोलिम निर्यातक देश संगठन द्वारा प्रस्तुत अंतर्राष्ट्रीय गैस एवं कोयला बाज़ारों में पारदर्शिता पर भी जेओडीआई-आयल डेटाबेस की प्रतीक्षा है जिस पर नवंबर में हमारे वित्त मंत्रियों द्वारा चर्चा की जाएगी। हमें नवंबर 2012 में मूल्य रिपोर्टिंग एजेंसियों के कार्यकरण तथा पर्यवेक्षण में सुधार पर आईओएससीओ की अनुशंसाओं की भी प्रतीक्षा है जिसे अन्य अधिदेशित संगठनों (आईईएफ़, आईईए और ओपीईसी) के सहयोग से प्रकाशित किया जाएगा। इस संबंध में ठोस उपाय करने के लिए वित्त मंत्रियों से कहा जाएगा।

विकास की चुनौतियों का समाधान

63. गरीबी उन्मूलन तथा ठोस, समावेशी, सतत एवं संतुलित विकास प्राप्त करना जी-20 विकास कार्यसूची के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। हम विकासशील देशों विशेषकर अल्प आय वाले देशों के साथ मिलकर कार्य करने की तथा उनकी राष्ट्रीय नीतियों एवं प्राथमिकताओं के कार्यान्वयन में उन्हें सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों खासकर सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।

64. हम जी-20 की पिछली बैठकों में किए गए कार्यों से आगे बढ़ने संबंधी विकास कार्यदल की पहल का स्वागत करते हैं। हम मेक्सिको की अध्यक्षता काल में खाद्य सुरक्षा, अवसंरचना तथा समावेशी हरित विकास जैसी प्राथमिकताओं का भी स्वागत करते हैं। हम सिओल बहुवर्षीय कार्य योजना में हमारी प्रतिबद्धताओं में हुई प्रगति की सराहना करते हैं तथा इसके साथ संलग्न विकास कार्य दल की वर्ष 2012 की प्रगति रिपोर्ट का समर्थन करते हैं। हम विकास कार्य दल को अगले शिखर सम्मेलन तक जी-20 विकास कार्रवाइयों के लिए आकलन और ज़िम्मेदारी सुनिश्चित करने हेतु एक प्रक्रिया बनाने जाने की संभावना का पता लगाने के लिए आमंत्रित करते हैं।

65. सतत आर्थिक विकास, गरीबी उपशमन और नौकरियों के सृजन के लिए अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः हम बहुपक्षीय विकास बैंकों की अनुशंसाओं, कार्य योजना तथा अवसंरचना पर उच्चस्तरीय पैनल की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन सहित बहुवर्षीय कार्य योजना के अंतर्गत हुई ठोस प्रगति का स्वागत करते हैं।

66. इस बात को स्वीकार करते हुए कि विकासशील देशों में अवसंरचना विकास परियोजनाओं का सार्वजनिक वित्त पोषण अनिवार्य है, हम मानते हैं कि इसे निजी क्षेत्र के निवेश द्वारा संपूरित किया जाना चाहिए। हम बहुपक्षीय विकास बैंकों को कार्य योजना के तहत आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और अल्प आय वाले देशों में जोखिम तथा लाभ संबंधी भ्रांतियों को दूर करने से संबन्धित रिपोर्ट का स्वागत करते हैं। इसमें जोखिमों से संबन्धित महत्वपूर्ण संदेश और प्रस्तावित अवसरों तथा अल्प आय वाले देशों में दीर्घावधिक अवसंरचना निवेश से संबन्धित जानकारियाँ शामिल हैं। त्वरित शहरीकरण के कारण उत्पन्न चुनौतियों और हमारे शहरों को सतत स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए हम विकासशील देशों के मध्यम एवं बड़े शहरों में शहरी जन परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाशित रिपोर्ट का स्वागत करते हैं और विकास कार्य दल की रिपोर्ट में निहित अनुवर्ती कार्रवाइयों का समर्थन करते हैं।

67. हम एमडीजी में निर्धारित विकास के लिए वैश्विक भागीदारी के प्रति प्रतिबद्ध हैं और प्रभावी विकास सहयोग के लिए वैश्विक भागीदारी, जिसका शुभारंभ बुसान, कोरिया में आयोजित सहायता प्रभाविता से सम्बद्ध चौथे उच्चस्तरीय मंच में प्राप्त सहमति के तत्वावधान में स्वेच्छिक भागीदारी के साथ किया जाना है, सहित अन्य तरीकों से इस प्रयोजनार्थ किए जा रहे प्रयासों का स्वागत करते हैं।

68. हम आपदा-प्रबंधन, जन-संरक्षण इत्यादि के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन उपकरणों और रणनीतियों के महत्व को स्वीकार करते हैं और साथ ही इनके आर्थिक प्रभावों के वित्तीय प्रबंधन को भी स्वीकार करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से डीआरएम पर होने वाली चर्चाओं में सूचनाएँ एवं व्यापक

भागीदारी उपलब्ध करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से किए जाने वाले विश्व बैंक और ओईसीडी के संयुक्त प्रयासों की सराहना करते हैं। हम जी-20 सदस्यों के समर्थन से इस क्षेत्र में देशवार अनुभवों पर विश्व बैंक तथा मेक्सिको के संयुक्त प्रकाशन का स्वागत करते हैं और हमें नवंबर तक पूर्ण की जाने वाली डीआरएम रणनीतियों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए ओईसीडी की स्वेच्छिक रूप रेखा का स्वागत है।

समावेशी हरित विकास के जरिये दीर्घावधिक समृद्धि का समवर्धन

69. वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के दीर्घावधिक विकास एवं समृद्धि के लिए हमें तात्कालिक आर्थिक संकट से आगे देखने की आवश्यकता है। हम ऐसे मार्गों का पता लगाने के महत्व को स्वीकार करते हैं जिनमें आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक समावेश एक दूसरे को संपूरित एवं संवर्धित करें। सतत विकास और गरीबी उन्मूलन के संबंध में समावेशी हरित विकास से विकास एवं आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिल सकती है जबकि पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक हित कल्याण को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिन बातों पर हमारा भविष्य निर्भर है। संरक्षणवादी उपायों को लागू करने के लिए समावेशी हरित विकास का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

70. हम विकासशील देशों को उपयुक्त उपायों के जरिये समर्थित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। इनमें वे कार्य भी शामिल हैं जो हरित विकास को बढ़ावा देते हैं। हम सतत विकास पर 2012 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में सतत विकास के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगे। अपनी जी-20 कार्यसूची के भाग के रूप में और रियो+20 तथा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय (यूएनएफ़सीसीसी) में हुई सहमति के अनुसार समावेशी हरित विकास पर विशेष बल देने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं।

71. विश्व अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता रहेगा और यदि अतिरिक्त योजना में विलंब होता है तो इसकी लागत में भी वृद्धि होगी। हम जलवायु परिवर्तन का मुक़ाबला करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों के पक्षकारों के 17वें सम्मेलन के परिणामों का स्वागत करते हैं। हम कानकुन एवं डरबन सम्मेलनों के निष्कर्षों का पूर्ण कार्यान्वयन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कोप 18 में सफल और संतुलित परिणाम प्राप्त करने के लिए आगामी अध्यक्ष कतर के साथ मिलकर कार्य करेंगे। हम मध्यम अवधि के दौरान विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जलवायु हितैषी मार्ग पर ले जाने की आवश्यकता पर बल देते हैं। हम जलवायु वित्त पर जी-20 अध्ययन दल बनाए जाने का स्वागत करते हैं ताकि कानकुन करार के अनुरूप यूएनएफ़सीसीसी के लक्ष्यों, प्रावधानों एवं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का प्रभावी उपयोग

करने के तरीकों पर विचार किया जाए। इस संबंध में हम नवंबर में वित्त मंत्रियों को एक रिपोर्ट सौपने के लिए कहेंगे। हम हरित जलवायु कोष को प्रचालित करने का भी समर्थन करते है।

72. विकास कार्य दल ने ऐसे अनेक व्यावहारिक एवं स्वेच्छिक उपायों पर चर्चा की जो विभिन्न देशों की परिस्थितियों एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप उन्हें सतत विकास के मार्ग पर बढ़ने में सहायता कर सकते हैं। हमारा मानना है कि विकासशील देशों की पहुँच उन संस्थाओं एवं तंत्रों तक होनी चाहिए जिनसे ज्ञान के आदान-प्रदान, संसाधनों को एकत्र करने तथा तकनीकी एवं संस्थागत क्षमता निर्माण हो सके जिसका उद्देश्य समावेशी हरित विकास एवं रणनीतियों को डिज़ाइन एवं कार्यान्वित करना है। हम हरित विकास ज्ञान मंच की शुरुआत करने में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का स्वागत करते हैं और इसमें रुचि रखने वाले देशों को उपयुक्त समर्थन देने के विकल्पों का पता लगाएंगे। हम समावेशी हरित विकास के लिए नीतिगत विकल्पों के एक स्वेच्छिक टूलकिट की सुपुर्दगी का स्वागत करते हैं और विकासशील देशों में समावेशी हरित विकास निवेश के लिए सार्वजनिक एवं निजी धन एकत्र करने के लिए प्रभावी तंत्रों का पता लगाए जाने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। इसमें समावेशी हरित निवेश पर सार्वजनिक-निजी संवाद मंच भी शामिल है। हम बी-20 के हरित विकास कार्यसंघ का स्वागत करते हैं।

73. हम इस बात पर बल देते हैं कि हरित विकास एवं सतत विकास के आधार पर दीर्घावधिक समृद्धि एवं हित कल्याण प्राप्त किया जा सकता है। हम ओईसीडी, विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा ढांचागत सुधार कार्यसूची में हरित विकास एवं सतत विकास नीतियों को शामिल किए जाने का स्वागत करते हैं। हम ढांचागत सुधार कार्यसूचियों में हरित विकास एवं सतत विकास को समेकित करने के लिए किए गए कार्यों पर स्वेच्छिक रिपोर्ट के जी-20 के प्रयासों को स्वीकार करते हैं। हम स्वेच्छिक आधार पर वर्ष 2013 में दोबारा रिपोर्ट देंगे। हम अपने उपयुक्त अधिकारियों को ढांचागत सुधार कार्य सूची में हरित विकास नीतियों को शामिल करने की दिशा में हुई प्रगति पर रिपोर्ट देने के लिए भी कहेंगे।

74. हम जीवाश्म ईंधन राज सहायता पर प्रगति रिपोर्ट का स्वागत करते हैं और अप्रभावी जीवाश्म ईंधन राज सहायता को तर्कसंगत बनाने एवं चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की दिशा में हुई प्रगति पर रिपोर्ट का स्वागत करते हैं। इस प्रकार की राज सहायता से व्यर्थ खपत को बढ़ावा मिलता है जबकि गरीब लोगों को लक्षित सहायता भी मिलती है। हम इस संबंध में हुई प्रगति की जानकारी अगले शिखर सम्मेलन में देने का अनुरोध अपने वित्त मंत्रियों से करते हैं और अगली बैठक तक जी-20 सदस्य देशों के लिए स्वेच्छिक समकक्ष समीक्षा प्रक्रिया हेतु विकल्पों का पता लगाने के उद्देश्य से ज़िम्मेदारी और पारदर्शिता की प्रासंगिकता को स्वीकार करते हैं। हम इस कार्य में शामिल अन्य एजेंसियों के साथ जीवाश्म ईंधन राज सहायता पर संवाद का भी स्वागत करते हैं।

75. कान में हमने हरित विकास की क्षमता को इष्टतम बनाने और हमारे देशों में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अल्प-कार्बन विकास रणनीतियों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अतः हम स्वच्छ ऊर्जा एवं ऊर्जा प्रभावी प्रौद्योगिकियों पर रिपोर्ट का स्वागत करते हैं और प्रौद्योगिकी उपयोग की चुनौतियों एवं राष्ट्रीय अनुभवों का आदान-प्रदान करने के जरिये इन प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा देने संबंधी जी-20 देशों के प्रयासों को स्वीकार करते हैं।

76. हम वैश्विक समुद्री पर्यावरण संरक्षण सर्वोत्तम प्रथा आदान-प्रदान तंत्र वेबसाइट की स्थापना का स्वागत करते हैं और हमें कान अधिदेश के अनुसरण में इसके शुभारंभ की प्रतीक्षा है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में गहनता में तेज़ी लाना

77. भ्रष्टाचार आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है, बाज़ारों की अखंडता को जोखिम में डालता है, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को क्षति पहुंचाता है, संसाधनों के आबंटन में विकृति पैदा करता है, जनता के विश्वास को नष्ट करता है तथा विधिसम्मत शासन को धक्का पहुंचाता है। हम सभी प्रासंगिक भागीदारों से भ्रष्टाचार का मुक़ाबला करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान करते हैं।

78. कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन के अंतरों को पाटना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है और हम सिओल जी-20 भ्रष्टाचार रोधी कार्ययोजना को कार्यान्वित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं। हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अधिसमय के अनुसमर्थन एवं पूर्ण कार्यान्वयन और स्वेच्छिक आधार पर रिश्वत से संबन्धित ओईसीडी कार्य योजना के साथ और भी सक्रिय कार्यकलाप करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। हम भ्रष्टाचार से लड़ने में बी-20 के सतत कार्यों का स्वागत करते हैं तथा हम समीक्षा तंत्र के विचारार्थ विषयों के अनुसरण में यूएनसीएसी समीक्षा प्रक्रिया में स्वेच्छिक आधार पर निजी क्षेत्र और सभ्य समाज को भी शामिल करना चाहते हैं। आज हम अपने देशों में भ्रष्ट अधिकारियों के प्रवेश को रोकने के लिए जी-20 भ्रष्टाचार-रोधी कार्यदल का समर्थन करते हैं और हम इस संबंध में सहयोग की रूप रेखाओं का विकास करेंगे। हम हितों के टकराव को रोकने, पहचानने एवं उपयुक्त तरीके से प्रबंधित करने के लिए संबन्धित अधिकारियों के लिए वित्तीय एवं संपत्ति खुलासा प्रणालियों के लिए कार्यकारी दल के सिद्धांतों का भी समर्थन करते हैं।

79. हम भ्रष्टाचार-रोधी विधान को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम अपने-अपने देशों के विधान के अनुरूप रिश्वत प्राप्त करने अथवा मांगने वाले और देने वाले लोगों पर कार्यवाही करेंगे। भ्रष्टाचार की जांच और अभियोजन में जी-20 और गैर जी-20 सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने में सहायता करने के लिए हम जी-20 देशों से पारस्परिक विधिक सहायता पर एक निर्देशिका का प्रकाशन करेंगे जिसमें जी-20 क्षेत्राधिकारों में परिसंपत्तियों का पता लगाने पर सूचना भी शामिल होगी।

हम भ्रष्टाचार के अर्थागमों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थलों से इंकार करने एवं चुराई गई परिसंपत्तियों की रिकवरी के संबंध में भी अपनी प्रतिबद्धता को नवीकृत करते हैं।

80. हम भ्रष्टाचार-रोधी कार्य दल के अधिदेश का दो वर्षों के लिए अर्थात 2014 तक विस्तार करते हैं और कार्यकारी दल से अनुरोध करते हैं कि एक व्यापक कार्य योजना तथा द्वितीय कार्यदल मानीटरिंग रिपोर्ट भी तैयार की जाए जिसे वर्ष 2012 के अंत तक शेरपाओं द्वारा विचारार्थ एवं अंगीकार किए जाने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

अन्य पैरा

81. चूंकि विश्व अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी है इसलिए जी-20 ने बहुपक्षीय सहयोग के एक नए प्रतिमान का नेतृत्व किया है जो वर्तमान एवं भावी चुनौतियों का प्रभावी तरीके से समाधान करने के लिए आवश्यक है। जी-20 के अनौपचारिक एवं लोचनीय स्वरूप से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय सहयोग का मार्ग सुविधाजनक हुआ है तथा विश्व अर्थव्यवस्था के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का मुक़ाबला करने में मदद मिली है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम जी-20 की पारदर्शिता एवं प्रभाविता में और सुधार करे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने में समर्थ हो। इस दिशा में एक योगदान के रूप में कान में की गयी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप शेरपाओं ने विकासशील जी-20 कार्यकारी प्रथाओं का एक सेट बनाया है।

82. फरवरी में लॉस काबोस में जी-20 देशों के विदेश मंत्रियों की एक अनौपचारिक बैठक हुई जिसमें इस बात पर चर्चा की गयी कि कैसे जी-20 के सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय अभिशासन की चुनौतियों का प्रभावकारी रूप से मुक़ाबला करने में अपना योगदान दे सकें।

83. जी-20 के निर्णयों के व्यापक प्रभाव को स्वीकार करते हुए हम मेक्सिकन अध्यक्षता द्वारा किए गए विस्तृत प्रयासों, जिनमें बिजनेस-20, लेबर-20, यूथ-20 तथा थिंक-20 शामिल हैं, का स्वागत करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र और अन्य पात्रों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर प्रयासों को बढ़ावा देंगे। कान अधिदेश के मद्देनजर यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी पहुँच अनुकूल तथा कारगर बनी रही, हम इस क्षेत्र में शेरपाओं द्वारा विकसित सिद्धांतों के एक सेट का स्वागत करते हैं।

84. हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र (यूएन), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़), विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन (डबल्यूटीओ), एफ़एसबी, आईएलओ, एफ़एओ और ओईसीडी शामिल हैं तथा सभ्य समाज का जी-20 प्रक्रिया में अपना योगदान देने के लिए धन्यवाद देते हैं। उनकी रिपोर्टों एवं

परामर्शों ने जी-20 चर्चाओं में दीर्घकालीन विकास के क्षेत्र से वित्तीय विनियम के क्षेत्र तक बहुमूल्य योगदान दिया।

समापन

85. 30 नवंबर तक मेक्सिको की अध्यक्षता के दौरान होने वाली शेष कार्यवाही पर हमारी नज़र रहेगी। रूस 1 दिसम्बर, 2012 को जी-20 की अध्यक्षता आरंभ करेगा। हम रूस की अध्यक्षता में सेंट पीटर्सबर्ग में मिलेंगे। हम एक सफल लॉस काबोस शिखर सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मेक्सिको का धन्यवाद करते हैं।